भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3899
जिसका उत्तर 04 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है
14 चैत्र, 1947 (शक)

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) का ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार

3899. श्री नीरज डांगी :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय और डिजिटल समावेशन में सुधार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) के विस्तार में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, विशेष रूप से डिजिटल भुगतान और सरकारी सेवाओं तक पहुंच के संबंध में, डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या पहल की गई है; और

(ग) डीपीआई को मजबूत करने में निजी क्षेत्र की भागीदारी की भूमिका क्या है, और क्या हाल ही में कोई सहयोग हुआ है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख) : भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने डिजिटल पहुंच, डिजिटल समावेशन, डिजिटल सशक्तीकरण सुनिश्चित करके और डिजिटल डिवाइड को पाटकर भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने की दृष्टि से 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम शुरू किया है।

भारत सरकार ने पहचान (आधार), भुगतान (यूपीआई), डेटा एक्सचेंज (डिजीलॉकर और एपीआई सेतु), आदि के लिए जनसंख्या स्तर पर आधारभूत डीपीआई को सफलतापूर्वक लागू किया है। डीपीआई भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास में एक परिवर्तनकारी शक्ति रही है, जिसने वित्तीय समावेशन, डिजिटल समावेशन, गवर्नेंस और आर्थिक विकास को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया है।

वित्तीय समावेशन, डिजिटल समावेशन में सुधार और आवश्यक सरकारी सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में डीपीआई का विस्तार करना भारत सरकार की प्रमुख प्राथमिकता रही है। सरकार का ध्यान प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आधारभूत डीपीआई की सफलता को दोहराने पर है, इसलिए ऋण, ई-कॉमर्स, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून और न्याय, लॉजिस्टिक्स, एमएसएमई, कृषि, सेवा वितरण, शहरी शासन आदि जैसे क्षेत्रों में नए डीपीआई पर काम किया जा रहा है और उन्हें बढ़ाया जा रहा है।

डिजिटल इंडिया पहल मोबाइल के माध्यम से सुलभ है और इसके कारण यह शहरी-ग्रामीण विभाजन को पाटती है। डिजिटल साक्षरता दर में सुधार करने के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण भारत में, भारत सरकार ने देश भर में 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों (प्रति परिवार एक व्यक्ति) को कवर करके ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता की शुरुआत करने के लिए "प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा)" नामक एक योजना लागू की है । सभी सरकारी

सेवाओं के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस (उमंग) चालू है और व्यक्तियों के लिए 2100 से अधिक सेवाएं प्रदान करता है। सेवा वितरण के सहायक मोड का समर्थन करने के लिए, देश भर में (ग्रामीण + शहरी) 5.97 लाख से अधिक सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) कार्यात्मक हैं, और ये केंद्र ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र के लोगों को उनके इलाके के निकट 800 से अधिक डिजिटल सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करते हैं। भारत के आम लोग डिजिटल इंडिया सेवाओं जैसे डिजिटल शिक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य, डिजिटल भुगतान, ई-कोर्ट सुविधाओं का उपयोग कहीं से भी और कभी भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, भाषिनी प्लेटफ़ॉर्म, एक राष्ट्रीय भाषा अनुवाद डीपीआई, भारत की विविध आबादी के लिए संचार बाधाओं को दूर करता है। यह वंचित समुदायों के लिए डिजिटल उपकरणों तक अधिक पहुँच को बढ़ावा देता है।

यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) अग्रणी डिजिटल भुगतान प्लेटफ़ॉर्म है, और यह प्रतिदिन 50 करोड़ लेनदेन की सुविधा प्रदान कर रहा है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया (एनपीसीआई) ने यूपीआई 123 पे और लाइटएक्स जैसी अभिनव यूपीआई सुविधाएँ शुरू की हैं, जिनका लक्ष्य कम इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में यूपीआई अपनाने को बढ़ावा देना है। इसके अलावा, जम्मू और कश्मीर एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित शहरों में डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचे का समर्थन करने के लिए जनवरी 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा सार्वजनिक बुनियादी ढांचा विकास कोष (पीआईडीएफ) का परिचालन किया गया था।

(ग): भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) ने सार्वजनिक निधि को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाले नवाचार के साथ जोड़कर डिजिटल नवाचार को फिर से परिभाषित किया है। आधार, यूपीआई और डिजिलॉकर जैसे प्लेटफ़ॉर्म नींव के रूप में काम करते हैं, जबकि संस्थाएँ उनके ऊपर एप्लिकेशन-विशिष्ट समाधान बनाती हैं। इस मॉडल को अब एआई के साथ बढ़ाया जा रहा है, जो वित्तीय और गवर्नेंस प्लेटफ़ॉर्मों में इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस को एकीकृत करता है। बैंकों, फिनटेक फर्मों और दूरसंचार प्रदाताओं के साथ साझेदारी ने वित्तीय समावेशन, डिजिटल पहचान समाधान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) संचालित सेवाओं को बढ़ाया है। डिजिलॉकर , यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई), उमंग, ई-साइन आदि जैसी कुछ प्रमुख पहलों में , निजी क्षेत्र की भागीदारी ने इन डीपीआई को सुदृढ़ करने और उनका प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

****